



विद्यालयी शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों के प्रति ग्रामीण एवं शहरी शिक्षकों के अभिमत का अध्ययन करना

शशि बाला

पीएच.डी. शोधार्थी, पेसिफिक एकेडमी ऑफ हायर एज्युकेशन, एण्ड रिसर्च विश्वविद्यालय, उदयपुर

डॉ. कौशिक पण्ड्या

शोध निर्देशक, प्रोफेसर, पेसिफिक एकेडमी ऑफ हायर एज्युकेशन एण्ड रिसर्च विश्वविद्यालय, उदयपुर

**Paper Received On:** 21 June 2024

**Peer Reviewed On:** 25 July 2024

**Published On:** 01 August 2024

### Abstract

यह शोध विद्यालयी शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों के प्रति ग्रामीण एवं शहरी शिक्षकों के अभिमत पर आधारित है। न्यादर्श हेतु उदयपुर, बाँसवाड़ा एवं चित्तौड़गढ़ जिले के 30 उच्च माध्यमिक विद्यालयों के 150 ग्रामीण एवं 150 शहरी शिक्षकों का चयन किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों के प्रति शिक्षकों के अभिमत हेतु स्वनिर्मित अभिमततावली का प्रयोग किया गया। दत्त विश्लेषण के लिए टी-परीक्षण सांख्यिकीय तकनीक का उपयोग किया गया। भोध के परिणाम स्पष्ट करते हैं कि ग्रामीण शिक्षकों ने शहरी शिक्षकों की तुलना में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन में आने वाली संभावित चुनौतियों का अधिक सामना किया है। विद्यालयी शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों के प्रति शहरी शिक्षक अधिक जागरूक हैं।

**मुख्य शब्द** – विद्यालयी शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, चुनौतियाँ आदि।

**समस्या की पृष्ठ भूमि, औचित्य एवं महत्त्व :-**

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निश्चित ही समर्थ भारत राष्ट्र के पुनःनिर्माण का योजनाबद्ध दस्तावेज़ है, जो वैश्विक पटल पर सन् 2030 के बाद की भारतीय भूमिका को यथार्थ स्वरूप प्रदान करता हुआ पथ साबित होगा। विद्यालयी शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों के प्रति शिक्षकों के अभिमतों का सामान्यीकरण किया जा सकेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियाँ ओर उसका समाधान सुदृढ़, सक्षम एवं समर्थ वैश्विक राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान होगा। युवा भारत राष्ट्र के भविष्य के गुणात्मक संवर्धन हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों के समाधान के साथ ही सन् 2030 तक के राष्ट्रीय

स्वप्नों, लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकेगा। सन् 2030 को ध्यान में रखते हुए मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा मंत्रालय), भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तुत की गई।

विद्यालयी शिक्षा प्रभाग में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा : सीखने की नींव, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान : सीखने के लिए एक तात्कालिक आवश्यकता पूर्व शर्त, सभी स्तरों पर शिक्षा की सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करना, अधिगम समग्र, आनंददायी एवं एकीकृत होना चाहिए, शिक्षक के दायित्व, समतामूलक एवं समावेशी शिक्षा, विद्यालय संगम के माध्यम से कुशल संसाधन एवं प्रभावी गवर्नेंस सुनिश्चित करना, विद्यालयी शिक्षा के लिए मानक निर्धारण और प्रत्यायन आदि बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए सन् 2030 तक के लिए राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित किए हैं। शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय लक्ष्यों को पाने एवं चुनौतियों के प्रति मार्गदर्शन हेतु शिक्षकों के अभिमत आवश्यक है। यह एक सावधानी युक्त क्रमबद्ध, वैज्ञानिक अध्ययन है जिसके निष्कर्ष सम्बन्धित पक्षों को आलोकित करते हैं।

#### शोध शीर्षक :-

विद्यालयी शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों के प्रति ग्रामीण एवं शहरी शिक्षकों के अभिमत का अध्ययन।

#### शोध के उद्देश्य :-

विद्यालयी शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों के प्रति ग्रामीण एवं शहरी शिक्षकों के अभिमत का तुलनात्मक अध्ययन करना।

#### समस्या का परिभाषीकरण :-

##### 1. विद्यालयी शिक्षा :-

कक्षा 11 एवं 12 में अध्ययनरत विद्यार्थियों एवं शिक्षण कार्य करवाने वाले शिक्षकों को विद्यालयी शिक्षा में सम्मिलित किया गया है।

##### 2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 :-

शिक्षा के सार्वभौमीकरण एवं गुणवत्तात्मक दृष्टिकोण से राष्ट्रीय जनसमुदाय हेतु उत्पादक शिक्षा का प्रारूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में नियोजित कर आदर्श, कुशल, संवेदनशील एवं उत्पादक भारतीय नागरिक तैयार कर वैश्विक परिदृश्य में अपनी प्रभावी पहल सुनिश्चित करने का भावी लक्ष्य रखा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कुशल क्रियान्वयन एवं रणनीति पर विद्यालयी शिक्षा सम्बन्धी अभिकरणों को सशक्त मार्गदर्शन प्रस्तुत करती है। सन् 2030 को ध्यान में रखते हुए मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा मंत्रालय), भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तुत की गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विद्यालय शिक्षा, उच्चतर शिक्षा, केन्द्रीय विचारणीय मुद्दे, क्रियान्वयन की रणनीति जैसे भागों में गुणवत्ता का स्तर और ऊपर उठाने के लिए विभिन्न प्रावधान किए गए हैं।

### 3. क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियाँ :-

विद्यालयी शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों से तात्पर्य पाठ्यचर्या भार, आकलन एवं मूल्यांकन, शिक्षा पर राष्ट्रीय नीतियों का प्रभाव, शिक्षा व्यवस्था पर वैश्वीकरण का प्रभाव, भाषायी विविधता, शिक्षा का निजीकरण एवं व्यावसायीकरण, आरक्षण नीति, स्वायत्तता एवं समुदाय से हैं। शोध कार्य के माध्यम से विद्यालयी शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के गुणात्मक संवर्धन हेतु संभावनाओं के आधार पर विविध अभिमतों का सामान्यीकरण किया जा सकेगा। साथ ही क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों के समाधान प्राप्त किए जा सकेंगे। इस शोध कार्य के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सन् 2030 तक की सम्भावनाओं को शैक्षिक जगत् तक पहुँचाने का प्रयास है। साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियाँ ओर उसका समाधान सुदृढ़, सक्षम एवं समर्थ वैश्विक राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान होगा।

#### परिसीमन :-

प्रस्तुत भोध कार्य को उदयपुर, बाँसवाड़ा एवं चित्तौड़गढ़ जिले के ग्रामीण एवं भाहरी 30 उच्च माध्यमिक विद्यालयों के 300 शिक्षकों तक ही सीमित रखा गया है।

#### न्यादर्श :-

यादृच्छिक प्रतिचयन विधि से न्यादर्श का चयन किया गया है। भोध अध्ययन में न्यादर्श के रूप में उदयपुर, बाँसवाड़ा एवं चित्तौड़गढ़ जिले के 30 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में से 300 शिक्षकों का चयन किया गया है। प्रत्येक जिले से 05 ग्रामीण एवं 05 शहरी कुल 10 विद्यालयों का चयन किया गया। प्रत्येक विद्यालय से 10 शिक्षकों का चयन किया गया।

#### विधि :-

प्रस्तुत भोध में सर्वेक्षण विधि का चयन किया गया।

#### उपकरण :-

प्रस्तुत अध्ययन में विद्यालयी शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों के प्रति शिक्षकों के अभिमत हेतु स्वनिर्मित अभिमतावली का प्रयोग किया गया।

#### सांख्यिकीय तकनीक :-

प्रस्तुत शोध कार्य में दत्त वि लेषण के लिए टी-परीक्षण सांख्यिकीय तकनीक को उपयोग में लिया गया।

#### परिकल्पना :-

विद्यालयी शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों के प्रति ग्रामीण एवं शहरी शिक्षकों के अभिमत में सार्थक अन्तर नहीं है।

दत्त विश्लेषण :-

**उद्देश्य संख्या-1** विद्यालयी शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों के प्रति ग्रामीण एवं शहरी शिक्षकों के अभिमत का तुलनात्मक अध्ययन करना।

विद्यालयी शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों के प्रति ग्रामीण एवं शहरी शिक्षकों के अभिमतों का विश्लेषण कर प्राप्त आंकड़ों की गणना की गई।

**सारणी संख्या 1**

विद्यालयी शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों के प्रति ग्रामीण एवं शहरी शिक्षकों के अभिमतों का मध्यमान, मानक विचलन तथा टी-मान के आधार पर क्षेत्रवार विश्लेषण

क्र. सं.	एनईपी क्रियान्वयन चुनौतियों के क्षेत्र	2020 संबंधी	ग्रामीण शिक्षक N <sub>1</sub> =150		शहरी शिक्षक N <sub>2</sub> =150		मध्य मान अन्तर D [Ste]	अन्तर की मानक त्रुटिσD [SED]	df	टी-मान	सार्वकता अन्तर
			मध्यमान	मानक विचलन	मध्यमान	मानक विचलन					
1	पाठ्यचर्या	भार	24.93	2.51	22.71	2.72	2.22	0.30	298	7.35	S
2	आकलन एवं मूल्यांकन		21.92	2.31	20.67	2.47	1.25	0.71	298	4.53	S
3	शिक्षा पर राष्ट्रीय नीतियों का प्रभाव		24.46	3.18	22.74	2.90	1.72	0.35	298	4.89	S
4	शिक्षा व्यवस्था पर वैश्वीकरण का प्रभाव		23.99	2.95	22.71	1.95	1.28	0.29	298	4.43	S
5	भाषायी विविधता		21.56	2.44	20.68	2.73	0.88	0.30	298	2.94	S
6	शिक्षा का निजीकरण एवं व्यावसायीकरण		16.82	2.56	16.08	2.77	0.74	0.31	298	2.40	S
7	आरक्षण नीति		17.24	2.01	17.86	2.02	-0.12	0.23	298	0.51	NS
8	स्वायत्तता एवं समुदाय		17.03	2.18	18.25	1.94	-1.22	0.24	298	5.12	S
समग्र			168.45	20.15	161.70	19.50	6.75	2.29	298	2.94	S

't' का सारणी मान = .01 = 2.59, .05 = 1.97

S = सार्थक अन्तर,

NS = सार्थक अन्तर नहीं



### व्याख्या –

समस्त क्षेत्रों के आधार पर विद्यालयी शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों के प्रति ग्रामीण एवं शहरी शिक्षकों के बीच अंतर का पता लगाने के लिए टी-अनुपात की गणना की गई। ग्रामीण शिक्षकों का मध्यमान 168.45 शहरी शिक्षकों के मध्यमान 161.70 से अधिक है। माध्य के बीच अंतर के लिए 0.01 स्तर पर सभी क्षेत्रों के प्राप्तियों का समग्र टी-मान 2.94 है। प्राप्त परिणामों के आधार पर ग्रामीण एवं शहरी शिक्षकों की विद्यालयी शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों के स्तर में भिन्नता है। ग्रामीण शिक्षकों ने शहरी शिक्षकों की तुलना में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन में आने वाली संभावित चुनौतियों का अधिक सामना किया है। इससे यह निष्कर्ष निकला कि विद्यालयी शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों के प्रति शहरी शिक्षक अधिक सकारात्मक है। आरेख में विद्यालयी शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों को तुलनात्मक रूप से दर्शाया गया है। अतः परिकल्पना “विद्यालयी शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों के प्रति ग्रामीण एवं शहरी शिक्षकों के अभिमत में सार्थक अन्तर नहीं है।” अस्वीकार की जाती है।

#### 1. प्रथम क्षेत्र : पाठ्यचर्या भार :-

विद्यालयी शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों के प्रथम क्षेत्र ‘पाठ्यचर्या भार’ के प्रति प्राप्त आंकड़ों का टी-मान 7.35 सारणी के टी-मान .01 स्तर पर 2.59 से अधिक है। ग्रामीण शिक्षकों का मध्यमान 24.93 शहरी शिक्षकों के मध्यमान 22.71 से अधिक है। प्राप्त परिणामों के आधार पर ग्रामीण एवं शहरी शिक्षकों के पाठ्यचर्या भार के स्तर में भिन्नता है। ग्रामीण शिक्षकों ने शहरी शिक्षकों की तुलना में पाठ्यचर्या भार संबंधी चुनौतियों का अधिक सामना किया है।

इससे यह निष्कर्ष निकला कि ग्रामीण शिक्षकों के अनुसार अनुभवात्मक शिक्षण और अवधारणा—उन्मुख शिक्षण चुनौतिपूर्ण कार्य है।

**2. द्वितीय क्षेत्र : आकलन एवं मूल्यांकन :-**

विद्यालयी शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों के द्वितीय क्षेत्र 'आकलन एवं मूल्यांकन' के प्रति प्राप्त आंकड़ों का टी-मान 4.53 सारणी के टी-मान .01 स्तर पर 2.59 से अधिक है। ग्रामीण शिक्षकों का मध्यमान 21.92 शहरी शिक्षकों के मध्यमान 20.67 से अधिक है। प्राप्त परिणामों के आधार पर ग्रामीण एवं शहरी शिक्षकों के आकलन एवं मूल्यांकन के स्तर में भिन्नता है। ग्रामीण शिक्षकों ने शहरी शिक्षकों की तुलना में आकलन एवं मूल्यांकन संबंधी चुनौतियों का अधिक सामना किया है। इससे यह निष्कर्ष निकला कि ग्रामीण शिक्षकों के अनुसार बालक के मानसिक विकास का बुद्धि लब्धि के आधार पर उपलब्धि परीक्षण कर मूल्यांकन करना चुनौतिपूर्ण है।

**3. तृतीय क्षेत्र : शिक्षा पर राष्ट्रीय नीतियों का प्रभाव :-**

विद्यालयी शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों के तृतीय क्षेत्र 'शिक्षा पर राष्ट्रीय नीतियों का प्रभाव' के प्रति प्राप्त आंकड़ों का टी-मान 4.89 सारणी के टी-मान .01 स्तर पर 2.59 से अधिक है। ग्रामीण शिक्षकों का मध्यमान 24.46 शहरी शिक्षकों के मध्यमान 22.74 से अधिक है। प्राप्त परिणामों के आधार पर ग्रामीण एवं शहरी शिक्षकों के शिक्षा पर राष्ट्रीय नीतियों का प्रभाव के स्तर में भिन्नता है। ग्रामीण शिक्षकों ने शहरी शिक्षकों की तुलना में शिक्षा पर राष्ट्रीय नीतियों का प्रभाव संबंधी चुनौतियों का अधिक सामना किया है। इससे यह निष्कर्ष निकला कि ग्रामीण शिक्षकों के अनुसार आधुनिक शैक्षिक प्रौद्योगिकी को अपनाया जाना चुनौतिपूर्ण है।

**4. चतुर्थ क्षेत्र : शिक्षा व्यवस्था पर वैश्वीकरण का प्रभाव :-**

विद्यालयी शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों के चतुर्थ क्षेत्र 'शिक्षा व्यवस्था पर वैश्वीकरण का प्रभाव' के प्रति प्राप्त आंकड़ों का टी-मान 4.43 सारणी के टी-मान .01 स्तर पर 2.59 से अधिक है। ग्रामीण शिक्षकों का मध्यमान 23.99 शहरी शिक्षकों के मध्यमान 22.71 से अधिक है। प्राप्त परिणामों के आधार पर ग्रामीण एवं शहरी शिक्षकों के शिक्षा व्यवस्था पर वैश्वीकरण का प्रभाव के स्तर में भिन्नता है। ग्रामीण शिक्षकों ने शहरी शिक्षकों की तुलना में शिक्षा व्यवस्था पर वैश्वीकरण का प्रभाव संबंधी चुनौतियों का अधिक सामना किया है। इससे यह निष्कर्ष निकला कि ग्रामीण शिक्षकों के अनुसार वैश्वीकरण का शिक्षा प्रणाली पर बहुआयामी प्रभाव चुनौतिपूर्ण है।

**5. पंचम क्षेत्र : भाषायी विविधता :-**

विद्यालयी शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों के पंचम क्षेत्र 'भाषायी विविधता' के प्रति प्राप्त आंकड़ों का टी-मान 2.94 सारणी के टी-मान .01 स्तर पर 2.59 से अधिक है। ग्रामीण शिक्षकों का मध्यमान 21.56 शहरी शिक्षकों के मध्यमान 20.68 से अधिक है। प्राप्त परिणामों के आधार पर ग्रामीण एवं शहरी शिक्षकों की भाषायी विविधता के स्तर में भिन्नता है। ग्रामीण

शिक्षकों ने शहरी शिक्षकों की तुलना में भाषायी विविधता संबंधी चुनौतियों का अधिक सामना किया है। इससे यह निष्कर्ष निकला कि ग्रामीण शिक्षकों के अनुसार पाठ्य पुस्तकों के निर्माण में मातृभाषा और अन्य भाषा के बीच शिक्षा के माध्यम में सामंजस्य करना चुनौतिपूर्ण है।

**6. षष्ठ क्षेत्र : शिक्षा का निजीकरण एवं व्यावसायीकरण :-**

विद्यालयी शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों के षष्ठ क्षेत्र 'शिक्षा का निजीकरण एवं व्यावसायीकरण' के प्रति प्राप्त आंकड़ों का टी-मान 2.40 सारणी के टी-मान .05 स्तर पर 1.97 से अधिक है। ग्रामीण शिक्षकों का मध्यमान 16.82 शहरी शिक्षकों के मध्यमान 16.08 से अधिक है। प्राप्त परिणामों के आधार पर ग्रामीण एवं शहरी शिक्षकों के शिक्षा का निजीकरण एवं व्यावसायीकरण के स्तर में भिन्नता है। ग्रामीण शिक्षकों ने शहरी शिक्षकों की तुलना में शिक्षा का निजीकरण एवं व्यावसायीकरण संबंधी चुनौतियों का अधिक सामना किया है। इससे यह निष्कर्ष निकला कि ग्रामीण शिक्षकों के अनुसार वर्तमान में प्राइवेट प्ले स्कूल की द्वारा प्रदत्त विभिन्न सुविधाओं एवं शैक्षणिक पाठ्यक्रमों के समकक्ष ऑनलाइन केन्द्रों को खड़ा करना चुनौतिपूर्ण है।

**7. सप्तम क्षेत्र : आरक्षण नीति :-**

विद्यालयी शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों के सप्तम क्षेत्र 'आरक्षण नीति' के प्रति प्राप्त आंकड़ों का टी-मान 0.51 सारणी के टी-मान .01 एवं .05 स्तर पर 2.59 एवं 1.97 से कम है। ग्रामीण शिक्षकों का मध्यमान 17.74 एवं शहरी शिक्षकों का मध्यमान 17.86 है। प्राप्त परिणामों के आधार पर ग्रामीण एवं शहरी शिक्षकों की आरक्षण नीति के स्तर में सार्थक अन्तर नहीं है। ग्रामीण शिक्षकों एवं शहरी शिक्षकों ने समान रूप से आरक्षण नीति संबंधी चुनौतियों का सामना किया है। इससे यह निष्कर्ष निकला कि शिक्षा में आरक्षण से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में कमी आती है।

**8. अष्टम क्षेत्र : स्वायत्तता एवं समुदाय :-**

विद्यालयी शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों के अष्टम क्षेत्र 'स्वायत्तता एवं समुदाय' के प्रति प्राप्त आंकड़ों का टी-मान 5.12 सारणी के टी-मान .01 स्तर पर 2.59 से अधिक है। शहरी शिक्षकों का मध्यमान 18.25 ग्रामीण शिक्षकों के मध्यमान 17.03 से अधिक है। प्राप्त परिणामों के आधार पर ग्रामीण एवं शहरी शिक्षकों के स्वायत्तता एवं समुदाय के स्तर में भिन्नता है। शहरी शिक्षकों ने ग्रामीण शिक्षकों की तुलना में स्वायत्तता एवं समुदाय संबंधी चुनौतियों का अधिक सामना किया है। इससे यह निष्कर्ष निकला कि शहरी शिक्षकों के अनुसार शिक्षक-शिक्षार्थियों में समुदाय की सेवा की भावना कम है।

**निष्कर्ष :-**

शोध निष्कर्षानुसार ग्रामीण एवं शहरी शिक्षकों की विद्यालयी शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों के स्तर में सार्थक अन्तर पाया गया है। ग्रामीण शिक्षकों ने शहरी शिक्षकों की तुलना में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन में आने वाली संभावित

चुनौतियों का अधिक सामना किया है। चुनौतियों के प्रति शहरी शिक्षक अधिक जागरूक है। अतः परिकल्पना “विद्यालयी शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों के प्रति ग्रामीण एवं शहरी शिक्षकों के अभिमत में सार्थक अन्तर नहीं है।” अस्वीकार की जाती है।

**1) पाठ्यचर्या भार संबंधी प्रमुख निष्कर्ष :-**

ग्रामीण शिक्षकों ने शहरी शिक्षकों की तुलना में पाठ्यचर्या भार संबंधी चुनौतियों का अधिक सामना किया है। ग्रामीण शिक्षकों के अनुसार अनुभवात्मक शिक्षण और अवधारणा-उन्मुख शिक्षण चुनौतिपूर्ण कार्य है।

**2) आकलन एवं मूल्यांकन संबंधी प्रमुख निष्कर्ष :-**

ग्रामीण शिक्षकों ने शहरी शिक्षकों की तुलना में आकलन एवं मूल्यांकन संबंधी चुनौतियों का अधिक सामना किया है। ग्रामीण शिक्षकों के अनुसार बालक के मानसिक विकास का बुद्धि लब्धि के आधार पर उपलब्धि परीक्षण कर मूल्यांकन करना चुनौतिपूर्ण है।

**3) शिक्षा पर राष्ट्रीय नीतियों का प्रभाव संबंधी प्रमुख निष्कर्ष :-**

ग्रामीण शिक्षकों ने शहरी शिक्षकों की तुलना में शिक्षा पर राष्ट्रीय नीतियों का प्रभाव संबंधी चुनौतियों का अधिक सामना किया है। ग्रामीण शिक्षकों के अनुसार आधुनिक शैक्षिक प्रौद्योगिकी को अपनाया जाना चुनौतिपूर्ण है।

**4) शिक्षा व्यवस्था पर वैश्वीकरण का प्रभाव संबंधी प्रमुख निष्कर्ष :-**

ग्रामीण शिक्षकों ने शहरी शिक्षकों की तुलना में शिक्षा व्यवस्था पर वैश्वीकरण का प्रभाव संबंधी चुनौतियों का अधिक सामना किया है। ग्रामीण शिक्षकों के अनुसार वैश्वीकरण का शिक्षा प्रणाली पर बहुआयामी प्रभाव चुनौतिपूर्ण है।

**5) भाषायी विविधता संबंधी प्रमुख निष्कर्ष :-**

ग्रामीण शिक्षकों ने शहरी शिक्षकों की तुलना में भाषायी विविधता संबंधी चुनौतियों का अधिक सामना किया है। ग्रामीण शिक्षकों के अनुसार पाठ्य पुस्तकों के निर्माण में मातृभाषा और अन्य भाषा के बीच शिक्षा के माध्यम में सामंजस्य करना चुनौतिपूर्ण है।

**6) शिक्षा का निजीकरण एवं व्यावसायीकरण संबंधी प्रमुख निष्कर्ष :-**

ग्रामीण शिक्षकों ने शहरी शिक्षकों की तुलना में शिक्षा का निजीकरण एवं व्यावसायीकरण संबंधी चुनौतियों का अधिक सामना किया है। ग्रामीण शिक्षकों के अनुसार वर्तमान में प्राइवेट प्ले स्कूल की द्वारा प्रदत्त विभिन्न सुविधाओं एवं शैक्षणिक पाठ्यक्रमों के समकक्ष ऑगनवाड़ी केन्द्रों को खड़ा करना चुनौतिपूर्ण है।



**7) आरक्षण नीति संबंधी प्रमुख निष्कर्ष :-**

ग्रामीण एवं शहरी शिक्षकों की आरक्षण नीति के स्तर में सार्थक अन्तर नहीं है। ग्रामीण शिक्षकों एवं शहरी शिक्षकों ने समान रूप से आरक्षण नीति संबंधी चुनौतियों का सामना किया है। शिक्षा में आरक्षण से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में कमी आती है।

**8) स्वायत्तता एवं समुदायसंबंधी प्रमुख निष्कर्ष :-**

शहरी शिक्षकों ने ग्रामीण शिक्षकों की तुलना में स्वायत्तता एवं समुदाय संबंधी चुनौतियों का अधिक सामना किया है। शहरी शिक्षकों के अनुसार शिक्षक-शिक्षार्थियों में समुदाय की सेवा की भावना कम है।

**शैक्षिक निहितार्थ :-**

ग्रामीण शिक्षकों ने शहरी शिक्षकों की तुलना में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन में आने वाली संभावित चुनौतियों का अधिक सामना किया है। भोध से प्राप्त परिणामों में कई महत्वपूर्ण निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं। जिनका यथोचित उपयोग विद्यालयी शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों के समाधान में किया जा सकता है।

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन में सबसे अधिक चुनौतियाँ शहरी अभिधारकों की अपेक्षा ग्रामीण शिक्षकों, को है। चुनौतियों के समाधान हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का क्रियान्वयन उद्देश्यानुसार प्रासंगिक, वैध, विश्वसनीय, कौशल आधारित और गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए।
2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन में चुनौतियों को कम करने के लिए अनुभवात्मक शिक्षण और अवधारणा-उन्मुख शिक्षण का चयन किया जाना चाहिए।
3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन हेतु निर्देशन कार्यक्रम, पर्यवेक्षण कार्यक्रम, पाठयोजना निर्माण, कक्षा शिक्षण कार्यक्रम पर विशेष जोर देना होगा। प्रौद्योगिकी हेतु डिजिटल क्लासरूम, दूरस्थ विशेषज्ञता-संचालित शिक्षण मॉडल, डिजिटल बुनियादी ढांचे को विकसित करने की आवश्यकता है।
4. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन में पाठ्यचर्या भार तथा आकलन एवं मूल्यांकन संबंधी चुनौतियों के प्रति शिक्षकों द्वारा छात्र अधिगम, विषय आधारित मूल्यांकन, विद्यालय स्तर पर आकलन, व्यावसायिक कौशल का विकास, व्यवहार और समझ पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम आधारित मूल्यांकन के प्रभावी क्रियान्वयन की आवश्यकता है।
5. शिक्षा पर राष्ट्रीय नीतियों का प्रभाव एवं वैश्वीकरण का शिक्षा प्रणाली पर नकारात्मक प्रभाव संबंधी चुनौतियों को कम करने के लिए सरकार द्वारा आधुनिक शैक्षिक प्रौद्योगिकी के अनुकूल विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए बेहतर शिक्षा और प्रशिक्षण में निवेश करना चाहिए।
6. वर्तमान में निजीकरण एवं व्यावसायीकरण संबंधी चुनौतियों को कम करने के लिए विभिन्न सुविधाओं एवं शैक्षणिक पाठ्यक्रमों के समकक्ष ऑनगनवाड़ी केन्द्रों को खड़ा करना आवश्यक है।

7. शिक्षा में आरक्षण के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में कमी आती है। अतः शिक्षक प्रशिक्षण एवं विकास में निवेश करके, पाठ्यक्रम का नियमित मूल्यांकन एवं अद्यतन करके, आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराकर, छात्रों एवं अभिभावकों से प्रतिपुष्टि प्राप्त करके शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सकती है। गुणवत्तायुक्त अकादेमिक अनुसंधान को उत्प्रेरित कर शोध की संस्कृति को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
8. विद्यालय के कामकाज को सुदृढ़ करने हेतु समुदाय से योग्य व प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के अस्थाई चयन में विद्यालय प्रमुख को निर्णय लेने की स्वायत्तता होनी चाहिए।
9. शिक्षक-शिक्षार्थियों में समुदाय की सेवा भावना विकसित होनी चाहिए। विद्यालयी पाठ्यक्रम सामुदायिक आवश्यकताओं के अनुकूल होने चाहिए।

### संदर्भ सूची

- कपिल, एच.के. (2006). *सांख्यिकी के मूल तत्व*, आगरा : विनोद पुस्तक मंदिर।
- ढौंडियाल, सच्चिदानंद; फाटक अरविंद (2003). *शैक्षिक अनुसंधान का विधिशास्त्र*, जयपुर : राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी।
- पाठक, पी.डी. तथा त्यागी, जी.एस. डी. (1967) : *भारतीय शिक्षा के आयोग*, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय (2020). *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*, नई दिल्ली, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा मंत्रालय), भारत सरकार।
- मिश्रा डॉ. महेन्द्र कुमार (2004): *शिक्षा सिद्धान्त एवं आधुनिक भारत की शिक्षा*, यूनिवर्सिटी बुक हाउस, जयपुर।
- सिन्हा, नीता (1989). *अध्यापक जवाबदेही एक विश्लेषण*, टेन्ड्रस एण्ड थोट्स इन एजुकेशन, इलाहाबाद।
- Agrwal J.C. (1989) : *National Policy on Education*, Delhi, Doba House.
- Agrwal J.C. (1990) : *Ramamurti Report on National Publicity on Education in India*, Delhi, Doba House.
- Agrwal J.C. (1992) : *Education Policy in India*, Delhi, Shipra Publication.
- Borg, Walter [1969] : *Educational Research-An Introduction*, New York : Longmans Green and Co. Ltd.
- Chaubey, S.P. (1956) : *Secondary Education for India*, New Delhi, Atma Ram and Sons.
- Govt. of India (1986) : *National Policy on Education-1986*, Ministry of Human Resource Development (Dept. of Education) New Delhi.
- Shukla, P.D.(1970) : *The New Education Policy in India*, New Delhi, Sterling Publication Pvt. Ltd.
- <https://www.education.gov.in> (India Ministry of Education)
- <https://www.myneep.in>
- <https://vikaspedia.in/education>
- <https://cscdigitalsevasolutions.com>